Irregular diversion of Milk by DMS depot Managers

148. SHRI SITARAM KESRI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware about the difficulties being faced by the people in the Capital in getting milk at DMS Depot because of the large supplies of milk being irregularly diverted to certain people in bulk for onward distribution to consumers on hefty commission;

(b) whether it is a fact that there is no effective control by officers on Depot Managers to check such malpractices or there is some collaboration between them and the distributors; and

(c) if so, what concrete steps are proposed to be taken to eliminate such irregular diversion of milk?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) The price of DMS milk being far below that of other suppliers in the market, there is very heavy demand for DMS milk, which brings considerable strain on DMS's milk distribution system. However special care has been taken to distribute DMS milk from its booths on first come first served basis. Residents Welfare Associations and Depot Advisory Committees are being increasingly associated with the distribution process so as to ensure fair distribution of milk.

दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सुविधायें

149. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्धन और सीमान्त किसानों को सुविधायें दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) और (ख) जी, हां।

दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन०पी०डी०पी०) के तहत प्रमुख आदानों पर गरीब तथा सीमान्त किसानों सहित सभी प्रकार के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, छोटे/सीमान्त किसानों को वरीयता दी जाती है। वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	केन्द्रीय आवंटन संशोधित/ सं०आ०	(रुपये लाख में) निर्मुक्तियां
1996-97	3543.00	3542.00
1997-98	3431.00	3431.00

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

अण्डों का उत्पादन

150. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मुर्गी के अंडों के उत्पादन का क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था और यह लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया;

(ख) क्या मुर्गी-दाना एवं अन्य औषधियों की कीमत अधिक होने के कारण मुर्गी के अंडों का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है; और

(ग) क्या भारत सरकार मुर्गी पालन व अंडा उत्पादन को उत्पादकों के लिए लाभ दायक व्यवसाय बनाने के लिए कोई योजना बना रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अण्डा उत्पादन का लक्ष्य 30 बिलियन था जिसकी तुलना में लगभग 28 बिलियन का लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

(ख) कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन कई बातों पर निर्भर करता है तथा आहार और दवाईयों की लागत उनमें से एक कारक है। आहार तथा दवाइयों के उच्च मूल्यों के

प्रभाव को कुक्कुट प्रबंधन में अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से निष्प्रभावी किया जा सकता है।

(ग) इस विभाग ने कुक्कुट पालन को लाभकारी उद्यम बनाने के उद्देश्य से विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए, पहले ही निम्नलिखित कदम उठाए हैं जिन्हें नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और सुदृढ़ किया जा रहा है.—

1. चार केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों के माध्यम से अण्डा और मीट किस्म के बेहतर चूजों तथा बलरूब चूजों को उपलब्ध कराना ताकि उन्हें विविधता प्रदान की जा सके और राज्य कुक्कुट फार्मों के माध्यम से उनका वितरण किया जा सके।

2. केन्द्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, उत्पादन को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है ताकि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कुक्कुट उत्पाद कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए निम्नतम स्तर के कार्यकर्ता उपलब्ध कराए जा सकें।

3. चार यादृच्छिक नमूना कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्रों तथा तीन क्षेत्रीय आहार विश्लेषण प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान के पोषक विंग के माध्यम से विभिन्न प्रजनन स्टॉकों के निष्पादन और आहार तथा आहर तत्वों के गुणवत्ता के परीक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

Central Assistance to Farmers of Tamil Nadu for Augmenting Agricultural Production

151. SHRI S. MUTHU MANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is that with a view to augmenting agricultural production, Central assistance is being provided to the farmers of Tamil Nadu for acquiring agricultural implements and machines under various crop specific programmes;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the other measures being taken by Government for augmenting agricultural production in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) Central assistance is being provided to the farmers of Tamil Nadu for procurement of various agriculture machines and equipments covering tractors, tillers, improved farm implements, plant protection equipments and water saving devices (drip and sprinkler irrigation sets) under various crop specific programmes covering rice, sugarcane, cotton oilseeds and pulses.

(c) Details are given at Statement.

Statement

List of Major Central/Centrally Sponsored Schemes under Implementation for Agriculture Development in Tamil Nadu

S.No.	Name of Schemes
1.	Integrated Cereal Development Programme - Rice
2.	Susbtainable Development of Sugarcane based Cropping System
3.	Intensive Cotton Development Programme
4.	National Pulses Development Project
5.	Oilseeds Production Programme
6.	Oil Palm Development Programme
7.	Accelerated Maize Development Programme
8.	National Watershed Development Project for Rainfed Areas
9.	National project on development of fertiliser use in low consumption areas
10.	Balanced and Integrated use of Fertilisers
11.	National Programme for Varietal Development
12.	Streamlining of certified Seeds production of important Indentified Vegetable Crops
13.	Promotion of Agricultural Mechanisation among Small Farmers
14.	Soil Conservation in the Catchments of River Valley Projects